advertising agency are utilised for Central Government advertising in the country. Public sector undertakings are required to confine their selection of agencies for handling their advertising to those included in the panel drawn up by the Directorate of Advertising and Visual Publicity on the basis of the following criteria :

(i) An agency must be entirely Indian-owned and Indian-controlled.

(ii) It must have carried on advertising business for a minimum period of one year and should have adequate professional skill to be able to handle national advertising accounts.

(iii) It must have reasonable financial resources i. e, a minimum paid-up capital of Rs. I lakh in the case of a limited liability company and a minimum of Rs. 50,000 actually committed to business in case of a proprietary or partnership firm.

(iv) It should have an annual turnover of not less than Rs. 3 lakhs.

(v) It should have advertising as its sole business occupation.

(vi) Its remuneration must be in the form of commission paid by various media owners and it must retain in full the commission thus earned without sharing it with or rebating it, to any client directly or indirectly.

An agency is also required to give an undertaking to the effect that it will not discriminate between non-Indian and Eastern Newspapers Society and Indian and Eastern Newspapers Society member papers either in the matter of agency commission or extension of credit facilities and that it will implement, to the extent possible, Government policy of encouraging the growth of medium and small categories of papers in consultation with D. A. V. P.

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

भूमि हथियाओ आन्दोलन के अन्तर्गत भूमिहीनों को स्वामित्व प्रदान करना

641. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या खाद्य, तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि हथियाओ आन्दोलन के अन्तर्गत देश में कितने भूमिहीनों को स्थायी आधार पर भूमि के वास्तविक स्वामित्व अधिकार प्रधान किये गए हैं और जिस भूमि के लिये इस प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये हैं, उसका कुल रकबा कितना है ; और

(ख) दिल्ली प्रशासन तथा अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपरोक्त प्रकार से जनता को जितनी भूमि के लिये स्वामित्व अधिकार दिये गये, उसका रकबा कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दैनिक "ट्रिब्यून" के विषय में प्रेस परिषद की राय

642. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री राम सिंह अयरपाल :

श्री रवि राय :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद् ने दैनिक समाचार पत्र "ट्रिब्यून" के बारे में अपनी राय व्यक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). ट्रिब्यून के सम्पादक ने हरियाणा सरकार के विरुद्ध जो